GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.63
ANSWERED ON 03.12.2021

RAILWAY PROJECTS IN ODISHA

63 SMT. MAMATA MOHANTA:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the present status of various ongoing/pending railway projects in Odisha;

(b) the steps taken by the Railways to complete the said projects in a time bound manner;

(c) whether Government of Odisha has proposed to bear some cost of the said projects for their timely completion and if so, the details thereof and the response of the Railways thereto;

(d) the number of railway projects in Odisha for which survey has been conducted and approved but for which work is not underway as yet;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the efforts made by Government to speed up the work?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (f): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (f) OF STARRED QUESTION NO. 63 BY SMT. MAMATA MOHANTA ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 03.12.2021 REGARDING RAILWAY PROJECTS IN ODISHA.

(a), (b), (d) to (f): Railway projects are sanctioned Zonal Railway-wise and not State-wise, as, Indian Railways' projects may span across State boundaries. However, as on 01.04.2021, 37 Railway Projects costing ₹55,219 crore for 4,643 km length, falling fully/partly in the State of Odisha are at different stages of planning/approval/execution, out of which, 928 km length has been commissioned and an expenditure of ₹16,903 crore has been incurred upto March, 2021.

Odisha is covered by East Coast Railway, South Eastern Railway and South East Central Railway. Zonal Railway wise details of projects including cost and expenditure are made available in public domain on Indian Railways website i.e. www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget) >Pink Book(Year) >Railway wise works Machinery & Rolling Stock Programme.

Railway has substantially increased budget allocations for Infrastructure projects & safety works, falling fully/partly in State of Odisha. Average annual Budget allocation for Infrastructure projects & safety works, falling fully/partly in State of Odisha, during 2014-19 has been enhanced to ₹4,126 crore per year from ₹838 crore per year (during 2009-14). Thus, the average budget allocation during 2014-19 is 392% more as compared to average allocation during 2009-14 (₹838 Cr/Year). These allocations have been enhanced to ₹4,568 crore in 2019-20 and ₹5,296 crore in 2020-21 which are 445% and 532% more than the average allocation of 2009-14 (₹838 Cr/Year) respectively. Total allocation of Budget has further been enhanced to ₹5,921 crore in 2021-22, which is the highest ever budget allocation for the State of Odisha and 607% more than the average of 2009-14 (₹838 Cr/Year).

The completion of any Railway project(s) depends on various factors like quick land acquisition by State Government, forest clearance by officials of forest department, deposition of cost share by State Government in cost sharing projects, priority of projects, shifting of infringing utilities, statutory clearances from various authorities, geological and topographical conditions of area, law and order situation in the area of project(s) site, number of working months in a year for particular project site due to climatic conditions etc. and all these factors affect the completion time of the project(s). Railways is making all the efforts for expeditious completion of projects.

Progress of project depends on timely land acquisition and forestry clearance by the State Government. Railway has made significant progress in the available land.

Various steps are taken by the Government for effective and speedy implementation of railway projects include (i) prioritisation of projects (ii) substantial increase in allocation of funds on priority projects (iii) delegation of powers at field level (iv) close monitoring of progress of projects at various levels, and (v) regular follow up with State Governments and concerned authorities for expeditious land acquisition, forestry and Wildlife clearances and for resolving other issues pertaining to projects.

There is substantial increase in rate of commissioning since 2014. During 2009-14, 267 km (56 km of New line, 83 km of Gauge conversion and 128 km of Doubling projects), falling fully/partly in the state of Odisha, have been commissioned at an average rate of 53.40 km per year. During 2014-21, 1031 km (251 km of New line and 780 km of Doubling projects), falling fully/partly in the state of Odisha, have been commissioned at an average rate of 147.29 km per year, which is 176% more than average annual commissioning achieved during 2009-14.

(c): Three projects of New lines have been sanctioned on commitment of cost sharing by the Govt. of Odisha, are:

(i) Khurda Road-Bolangir new line project (289 km): Cost sharing by Govt. of Odisha for a length of 177 km in this project.

(ii) Jeypore-Navarangpur new line project (41 Km).

(iii) Jeypore-Malkangiri new line project (130 Km).

*****

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

03.12.2021 के

तारांकित प्रश्न सं. 63 का उत्तर

ओडिशा में रेलवे परियोजनाएं

***63 श्रीमती ममता मोहंता:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ओडिशा में रेलवे की चल रही/लंबित विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या ओडिशा सरकार ने उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उनकी कुछ लागत वहन करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ओडिशा में कितनी परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण कराया जा चुका है और इनका अनुमोदन भी हो चुका है लेकिन जिनका कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कार्य में तेजी लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

ओडिशा में रेलवे परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 03.12.2021 को राज्य सभा में श्रीमती ममता मोहंता के तारांकित प्रश्न सं.63 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित **विवरण।**

(क), (ख), (घ) से (च): रेल परियोजनाएं राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार स्वीकृत की जाती हैं, क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार, ओडिशा राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 4,643 कि.मी. लंबाई की 37 रेल परियोजनाएं, जिनकी लागत 55,219 करोड़ रु. है, योजना/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 928 कि.मी. लंबाई पर यातायात शुरू कर दिया गया है और मार्च, 2021 तक 16,903 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

ओडिशा, पूर्व तट रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में शामिल है। परियोजनाओं की लागत और व्यय सहित परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेलवे-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board >About Indian Railways >Railway Board Directorates >Finance (Budget) >Pink Book (Year) >Railway wise works Machinery & Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

रेलवे ने ओडिशा राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। वर्ष 2014-19 के दौरान ओडिशा राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन को 838 करोड़ रु. प्रति वर्ष (2009-14 के दौरान) से बढ़ाकर 4,126 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार, 2014-19 के दौरान औसत बजट आबंटन 2009-14 (838 करोड़ रु. प्रति वर्ष) के दौरान औसत आबंटन की तुलना में 392% अधिक है। 2019-20 में इन आबंटनों को बढ़ाकर 4,568 करोड़ रुपये और 2020-21 में 5,296 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 2009-14 (838 करोड़ रु. प्रति वर्ष) के औसत आबंटन से क्रमश: 445 प्रतिशत और 532 प्रतिशत अधिक है। बजट के कुल आबंटन को 2021-22 में बढ़ाकर 5,921 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो ओडिशा राज्य के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट आबंटन है और 2009-14 (838 करोड़ रु. प्रति वर्ष) के औसत से 607% अधिक है।

किसी रेल परियोजना (परियोजनाओं) का समय पर पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत की हिस्सेदारी जमा कराना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक

स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना (परियोजनाओं) क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना (परियोजनाओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं। रेलवे द्वारा परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

परियोजना की प्रगति राज्य सरकार द्वारा समय पर भूमि अधिग्रहण और वानिकी मंजूरी पर निर्भर करती है। रेलवे ने उपलब्ध भूमि में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों में (i) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (ii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि (iii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (iv) विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की प्रगति की गहन निगरानी और (v) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

वर्ष 2014 से यातायात शुरू करने की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-14 के दौरान ओडिशा राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 267 कि.मी. (56 कि.मी. नई लाइन, 83 कि.मी. आमान परिवर्तन और 128 कि.मी. दोहरीकरण परियोजनाएं) को 53.40 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर पर यातायात के लिए खोल दिया गया है। वर्ष 2014-21 के दौरान, ओडिशा राज्य में पूर्णतया/आंशिक रूप से पड़ने वाली 1031 कि.मी. (251 कि.मी. नई लाइन और 780 कि.मी. दोहरीकरण परियोजनाएं) को प्रति वर्ष 147.29 कि.मी. की औसत दर पर यातायात के लिए खोल दिया गया है, जो 2009-14 के दौरान प्राप्त किए गए औसत वार्षिक कमीशनिंग से 176% अधिक है।

(ग): ओडिशा सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी की वचनबद्धता के आधार पर तीन नई लाइन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(i) खुर्दा रोड-बोलनगीर नई लाइन परियोजना (289 कि.मी.): इस परियोजना के लिए ओडिशा सरकार 177 कि.मी. लंबाई के लिए लागत में हिस्सेदारी कर रही है।
(ii) जेपोर-नवरंगपुर नई लाइन परियोजना (41 कि.मी.):
(iii) जेपोर-मलकानगिरी नई लाइन परियोजना (130 कि.मी.):

*****

श्रीमती ममता मोहंता : उपसभापति महोदय, मेरे मयूरभंज जिले में रेल विकास को हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है, जो कि ओडिशा का सबसे बड़ा आदिवासी बहुल जिला है। बांगिरिपोसी से गोरुमहिषाणी तक, केवल 42 किलोमीटर की missing line जोड़ना अभी भी बाकी है। मयूरभंज जिले की सामाजिक एवं आर्थिक अभिवृद्धि के लिए बांगिरिपोसी से गोरुमहिषाणी तक रेल लाइन जोड़ना बहुत जरूरी है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इस बांगिरिपोसी से गोरुमहिषाणी रेल लाइन को कब स्वीकृति मिलेगी और इसे कब जोड़ा जाएगा?

श्री अश्वनी वैष्णव : उपसभापति महोदय, ओडिशा में 2009 से 2014 तक रेलवे बजट में on an average 838 करोड़ का allocation होता था और 2014 से 2019 में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में यही संख्या 392 प्रतिशत बढ़कर 4,126 करोड़ प्रति वर्ष हो गई। माननीय सदस्या जो कह रही हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ओडिशा के प्रति कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ओडिशा के लिए एक बहुत विशेष स्थान है। प्रधान मंत्री जी का जो पूर्वोदय का विज़न है, उसमें ओडिशा, वैस्ट बंगाल, नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स, इनके लिए विशेष स्थान है। माननीय सदस्या जिस specific project के बारे में कह रहीं हैं, मैं निवेदन करूँगा कि आप कभी भी मेरे साथ चर्चा के लिए आएं, तब हम उस specific project की details के बारे में चर्चा कर सकते हैं।

श्रीमती ममता मोहंता : उपसभापति महोदय, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुत् नवीन पटनायक जी रेल लाइन के लिए मुफ्त में जमीन देने की घोषणा कर चुके हैं। Budhamara से Chakulia रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति भी मिली थी, फिर भी कार्य शुरू नहीं हुआ। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि Badampahar से Keonjhar एवं Budhamara से Chakulia को रेल लाइन से कब तक जोड़ा जाएगा?

श्री अश्वनी वैष्णव : उपसभापति महोदय, Budhamara से Chakulia की जो नई लाइन है, वह 55 किलोमीटर की है। यह लाइन ओडिशा और झारखंड से गुजरती है, जिसमें झारखंड का 38 किलोमीटर का सेक्शन है और ओडिशा का 17 किलोमीटर का सेक्शन है। सर, इस नई रेलवे लाइन का सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे होने के बाद दोनों राज्यों के साथ निवेदन चल रहा है कि आप land acquisition के लिए जल्दी-से-जल्दी सुविधा प्रदान करें और साथ ही, forest के लिए जो approvals हैं, उन्हें भी पूरा करें। जैसा कि मोदी जी ने कहा - 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास' भी लगेगा तो निश्चित तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे, हम उन्हें दोनों राज्यों के साथ मिलकर करेंगे।

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, the hon. Minister, in his reply, has stated about three projects of new railway lines on commitment of cost-sharing by the Government of Odisha. One, among these three, is Khurda Road--Bolangir new line project of 289 kms. So far as my knowledge goes, this is not a new project. Khurda road-Bolangir new line is an ongoing project for more than last 15 years. The hon. Minister

has rightly stated that the construction progress of railway line has gone up from 2014 to 2021, and 176 per cent, more than annual average, commissioning had been achieved in 2009 and 2014. I would like to know from the hon. Minister what the timeframe for the completion of this oldest ongoing rail project in Odisha, that is, Khurda Road-Bolangir, under the East Coast Railways, is.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, would you allow me to answer in Odia?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, Khurda-Bolangir line* * 'Sir, Khurda -Balangir line is very important for Odisha. This line is called a 'new line' because there was no railway line there earlier and therefore, it is a new project, though, it has been under construction for quite some time. In this project...'

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the translation must be available.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Okay, Sir. I will speak in Hindi. No problem. ...(*Interruptions*)...

AN HON. MEMBER: You can speak in Odia. ...(*Interruptions*)...

SHRI ASHWINI VAISHNAW: *'In this project, the important factors are land acquisition and forest clearances. Wherever land has been acquired and forest clearances received, there the project is being implemented speedily. I mean to say that regular updating and progress monitoring is taking place. As you know, at the field level....'

Sir, there is a very important line, Talcher-Angul. उसके tunnel का *जो portion था, that tunnel portion has been completed in the recent times. So, the progress is very good in almost all the projects in Odisha. I request if there is any other problem, any hon. Member can come and have a separate discussion with me.

श्री उपसभापति : श्रीमती सीमा द्विवेदी।

---

* English translation of the original speech delivered in Odia.

* English translation of the original speech delivered in Odia.

श्रीमती सीमा द्विवेदी : माननीय उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर मानव-रहित रेलवे क्रॉसिंग्ज़ हैं, जिनके फाटक छः बजे के बाद बन्द हो जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि क्या आप इन सब की जाँच कराकर उनको एक नये सिरे से बनवाने का प्रयास करेंगे? यह एक बात हुई, अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि...

श्री उपसभापति : नहीं, आप एक ही सवाल पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सीमा द्विवेदी : सर, यह इसी से संबंधित है। ...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : एक मिनट, प्लीज़। यह सवाल ओडिशा से रिलेटेड है, आप उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रही हैं। माननीय मंत्री जी चाहें, तो जवाब सकते हैं, नहीं तो जो क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होना चाहिए।

श्रीमती सीमा द्विवेदी : ठीक है, सर। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : श्री जुगलसिंह लोखंडवाला।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : सर, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 'रामायण' ट्रेन शुरू की है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऐसी कोई और ट्रेन चालू करने वाले हैं?

श्री उपसभापति : यदि ओडिशा से संबंधित आपका कोई सवाल हो, तो उसे आप माननीय मंत्री जी से पूछें।

श्री जुगलसिंह लोखंडवाला : नहीं सर। थैंक यू।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 64